

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

दि. 68-PBR-16



लोकेन्द्र सिंह आ०श्री छतर सिंह  
निवासी ग्राम पतलई कलौ तह०  
डोलरिया जिला होशंगाबाद

पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

हरप्रताप सिंह आ० मनमोहन सिंह  
निवासी ग्राम पतलई कलौ तह० डोलरिया  
जिला होशंगाबाद

उत्तरदाता

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्त्ता यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय डोलरिया द्वारा राजस्व सीमाकन प्रकरण क 69अ/12 वर्ष 2010.11 ग्राम पतलईकला तह० डोलरिया जिला होशंगाबाद हरप्रताप सिंह बनाम सर्वसाधारण मे पारित आदेश दिनांक 24.03.14 एवं न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के राजस्व प्रकरण कं 02 अ/12 वर्ष 2014-15 लोकेन्द्र सिंह बनाम हरप्रताप सिंह में पारित आदेश दिनांक 02.07.2015 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष बिना किसी बिलम्ब के प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य

यह कि पुनरीक्षणकर्त्ता एवं उत्तरदाता ग्राम पतलई कलौ तह० डोलरिया जिला होशंगाबाद के स्थायी निवासी होकर कास्तकार हैं मनमोहन सिंह द्वारा धारा 129 म.प्र.भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश कर प्रश्नाधीन भूमि ग्राम पतलईकलौ तह०डोलरिया जिला होशंगाबाद खसरा नं. 16/ रकबा 1248.14

श्रीमान राजस्व मण्डल  
ग्वालियर  
दि. 30/12/15  
श्री लोकेन्द्र सिंह  
नं. 537  
25/1

CF 27-1-16


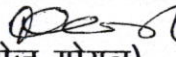
JK



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 68-पीबीआर/16

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-1-2016	<p>आवेदक एवं केवियटकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 2-7-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-3-14 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-7-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 2-7-2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 24-3-14 निरस्त कर दिया गया है, और अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि वर्तमान में प्रचलित है । अतः एक ही आदेश के विरुद्ध अपील लंबित होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अपर आयुक्त प्रकरण में अंतिम निर्णय करने के बाद पक्षकार को नियमानुसार निगरानी/अपील का अवसर उपलब्ध रहेगा ।</p>	<p>  (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>